सचिन पायलट ने बुधवार सुबह अपने निवास पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्यायें सुनीं।

जोधपुर हत्याकांड मामले में सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया

संसदीय कार्यमंत्री धारीवाल का कहना था कि, मृतक के भतीजे पप्पूराम ने जमीनी विवाद में 6 माह के मासूम समेत 4 लोगों की हत्या की है

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 19 जुलाई। जोधपुर के ओसियां विधानसभा क्षेत्र के चिरई गांव में मंगलवार मध्य रात्रि 6 माह के मासूम समेत 4 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में राज्य सरकार ने सदन में अपना जवाब रखा। मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि अब तक जो अनुसंधान हुआ है, उसमें सामने आया है कि हत्या पप्पूराम ने की है, जो मृतक पुनाराम का सगा भतीजा है। मंत्री के इस जवाब पर नाराजगी जताते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि क्या एक नाबालिग को पकड़ने पर सारे मुलजिम पकड़े गए? जब सुबह 4:30 बजे की घटना थी, तो पुलिस कितने घंटे बाद वहां पहुंची थी। एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार करके क्या सारे मुलजिम गिरफ्तार हो गए? मंत्री के जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया।

इससे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में कहा कि आरोपी पप्पूराम ने जमीनी विवाद और 6 महीने पहले सूरत में अपने भाई की संदिग्ध

- इस जवाब पर नाराजगी जताते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, क्या एक नाबालिग को पकड़ने पर सारे मुलजिम पकड़े गए। जब सुबह 4:30 बजे की घटना थी, तो पुलिस कितने घंटे बाद वहां पहुंची थी।
- गौरतलब है कि, जोधपुर में ओसियां के चिरई गांव में मंगलवार मध्यरात्रि को 6 माह के मासूम बच्चे सहित 4 लोगों की हत्या हुई थी, जिस पर विधायकों ने दिन भर सरकार को सदन में घेरा।

मौत होने की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। पप्पूराम की उम्र 19 वर्ष बताई जाती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए न केवल जोधपुर महानिरीक्षक और जोधपुर पुलिस अधीक्षक बल्कि जोधपुर कलेक्टर तथा संभागीय आयुक्त और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। मौके पर एफएसएल की टीम, अनुसंधान अधिकारी, साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान कर साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। मृतकों का मौके पर ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है।

सरकार की ओर से जवाब आने के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी बात रखनी चाही तो उन्हें सभापति राजेंद्र पारीक ने रोक दिया। सभापति का कहना था कि इस विषय पर केवल सरकार का जवाब आना था, चर्चा नहीं होनी थी। इस पर सदन में भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होकर भी मैं विपक्ष की तरफ से सवाल नहीं कर पाऊंगा, तो फिर हम कहां जाएंगे, यह लोकतंत्र को छोटा करने की बात है।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था चरमराई हुई है। आम आदमी दहशत में जिंदगी जी रहा है। राठौड़ ने अपने दल के साथ यह कहते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया कि यह पहली घटना नहीं बल्कि इस तरह की लोमहर्षक घटना रोज राजस्थान में घटित हो रही है। उन्होंने सवाल खड़े किए कि जब सुबह 4:30 बजे की घटना थी, तो पुलिस कितने घंटे बाद वहां पहुंची थी। एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार करके क्या सारे मुलजिम गिरफ्तार हो गए, हम इस जवाब से असंतुष्ट हैं।

रेलवे जनरल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुलचे/भटूरे, पावभाजी, मसाला डोसा शामिल है।

आरंभ में यह सेवा 64 स्टेशनों पर शुरू की गई है। अभी 54 में सेवा शुरू हो चुकी है और बाकी में शुरू की जा रही है। इस में हर प्लेटफॉर्म पर आगे और पीछे जनरल कोच के सामने इस भोजन के स्टॉल लगाए जाएंगे।

मैरिटल रेप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली, 19 जुलाई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करने (मैरिटल रेप) को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के शीघ्र सुनवाई के अनुरोध पर कहा कि संविधान पीठ द्वारा पहले से सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ उस याचिका पर सुनवाई करेगी।

पीठ ने अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के विशेष उल्लेख के दौरान इस मामले को उठाने पर कहा,हमें मैरिटल रेप से संबंधित मामलों को हल करना होगा।

अधिवक्ता जयसिंह दावा किया कि उनका मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय एक फैसले से जुड़े बाल यौन शोषण मामले से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के तहत अपवाद के बावजूद उच्च न्यायालय ने पति के खिलाफ बलात्कार के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। व्यक्ति के खिलाफ आरोप फॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध से भी संबंधित है।शीर्ष अदालत ने मैरिटल रेप (पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना) को अपराध घोषित करने और आईपीसी के प्रावधान से संबंधित याचिकाओं पर इस साल जनवरी में केंद्र से जवाब मांगा था। ये प्रावधान पत्नी के वयस्क होने पर जबरन यौन संबंध के लिए अभियोजन के खिलाफ पति को सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत का पासपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हुआ

नई दिल्ली, 19 जुलाई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2023 के पासपोर्ट रैंकिंग की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में टॉप पर सिंगापुर का नाम है जो विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट है. सिंगापुर ने जापान को पछाड़ कर इस ताज को हासिल किया है। सिंगापुर के पासपोर्ट के जरिए कुल 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री ली जा सकती है। वहीं भारतीय पासपोर्ट के रैंकिंग की बात करें तो इसमें भी पिछले साल के मुकाबले बहुत सुधार हुआ है। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में कुल पांच स्थान का सुधार होकर यह 80वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट ने इस साल अपनी रैंकिंग में पांच पायदान का सुधार किया है और यह 80वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही भारतीयों को दुनिया के 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत के साथ इस लिस्ट में 80वें स्थान पर टोगो और सेनेगल जैसे देश का नाम भी शामिल है।

उत्तराखण्ड में करंट लगने से 16 लोगों की मौत, छः अन्य झुलसे

चमोली/देहरादून 19 जुलाई (वार्ता)। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार को एक बड़े हादसे में करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई है तथा छह अन्य घायल हो गये। घायल जल संस्थान के जेई समेत दो लोगों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। इस घटना के बाद से चमोली बाजार से लेकर गोपेश्वर तक अफरा तफरी का माहौल है।

बताया जा रहा है कि बीती रात को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से एक कर्मी की मौत हो गई थी। उसके बाद प्लांट से एक फेज पर बिजली गुल हो गई थी। बुधवार को घटना की सूचना पर स्थानीय लोग और पुलिस कर्मी मौके पर गए थे। इस घटना से बेखबर बिजली विभाग के कर्मियों ने बुधवार को सुबह

- नमामि गंगे प्रोजैक्ट के सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट में यह हादसा हुआ, रात भर से गुल बिजली सुबह जैसे ही लौटी उस लोकेशन पर मौजूद लोग एक के बाद एक करंट की चपेट में आते चले गये।
- जानकारी के मुताबिक, कुछ लोगों की मौत एक-दूसरे की जान बचाने और उसे देखने जाने के दौरान हो गई।

जैसे ही बिजली खोली तो एक के बाद एक करंट पर चिपक गया, कुछ लोगों ने भागकर जान बचाई जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा कुछ लोगों ने अलकनंदा में छलांग मारी, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए और घायलों को एक-एक लाख रुपए की सहायता राशि अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घायलों को एम्स ऋषिकेश हेलीकॉप्टर से लाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दी गईं है।

उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार को नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर विद्युत करंट से पुलिस कर्मियों सहित 16 लोगों की मृत्यु और छह अन्य के घायल होने के मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। इस सन्दर्भ में चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि आज समय लगभग 11:30 बजे नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर विद्युत करंट लगने से अधिक संख्या में जन हानि एवं जान-माल की क्षित हुई है, जिसकी मजिस्ट्रीयल जॉच करायी जानी नितान्त आवश्यक है। जांच मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया गया है।

सियाचिन में सेना के टैंट में आग लगी

नयी दिल्ली 19 जुलाई (वार्ता)। लद्दाख के सियाचिन में बुधवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक टेंट में आग लगने से सेना के एक कैप्टन की मौत हो गयी जबकि एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित तीन अन्य सैनिक घायल हो गये। हादसे में तीन कुली भी झुलस गये। घायल सैनिकों को उपचार के लिए अस्पाल में भर्ती कराया गया है। सेना के अनुसार यह हादसा आज तड़के हुआ तथा सैनिक आग की चपेट में आने से झुलस गये। घायलों की हालत स्थिर है और उनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

- इस घटना में सेना के एक कैप्टन की मौत हो गयी, जबकि एक लैफ्टिनेंट कर्नल सहित तीन अन्य सैनिक घायल हो गये।

'अमेरिका व चीन के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से पहले ग्रेट ब्रिटेन व जर्मनी एक दूसरे से आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे दोनों के बीच भारी व्यापार होता था। पर वे एक दूसरे को गलत समझते थे। ब्रिटिश सोचते थे कि जर्मनी यूरोप पर दबदबा बनाना चाहता है वहीं जर्मनी को लगता था कि ब्रिटिश उन्हें एक बड़ी ताकत के रूप में मान्यता दिए जाने में रोड़ा अकटा रहे हैं। और दोनों इस गलतफहमी को तब तक बढ़ाते रहे जब तक युद्ध के दौरान मैदान में आमने-सामने नहीं हो गए।

चाइनीज़ ग्लोबल टाइम्स को दिए एक इन्टरव्यु में श्वाट्र्ज कहते हैं कि किसिंजर को चिंता है कि अमेरिका ने चीन को अपना नम्बर वन दुश्मन मान लिया है और चीन ने भी अमेरिका को दुश्मन मान लिया है। यह एक खतरनाक स्थिति है।

अमेरिका-चीन युद्ध की संभावना पर श्वाट्र्ज कहते हैं कि दोनों के बीच टकराव की संभावना है, क्योंकि दोनों का सरकारी तंत्र अलग व्यवस्था पर आधारित है। उनकी अलग-अलग दार्शनिक सोच है, दोनों देश एक दूसरे को अपवाद मानते हैं।

वे कहते हैं कि किसिंजर ने अपनी किताब "ऑन चाइना" में यही कहा है कि दोनों देश खुद को एक महान सभ्यता मानते हैं। अमेरिका खुद को एक आदर्श व्यवस्था मानता है और उसने पूरी दुनिया को अपनी सामाजिक व सरकारी व्यवस्था देने की कोशिश की है। चीन भी खुद को महान सभ्यता मानता है और उसे लगता है कि उसे विश्व के लिए मॉडल होना चाहिए।

श्वाट्र्ज के अनुसार अभी रिश्ते बहुत खराब हैं, पर मुझे लगता है कि यह स्थिति शीत युद्ध के दौर से अलग है तब अमेरिका, रूस एकदम अलग थे। उनमें ना व्यापार होता था, ना परस्पर निवेश और ना ही कोई यात्रा होती थी। यहाँ तक कि दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। अमेरिका व चीन की अर्थव्यवस्थाएं और राजनैतिक घटनाक्रम गत 30 सालों से परस्पर जुड़ा हुआ है। इसलिए दोनों देशों को पारस्परिक मतभेद दूर करना ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, कम से कम वे यह तो मान ही सकते हैं कि प्रत्यक्ष टकराव का कोई कारण नहीं है और मतभेद सुलझाएं जा सकते हैं।

उन्होंने माना कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दे बहुत कठिन हैं खासकर ताईवान, मानवाधिकार व अन्य विषयों पर। थॉमसन का कहना है कि ये सभी मसले बिना किसी टकराव के सुलझाएं जा सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि एक बुद्धिमतापूर्ण समझ बनाना और वार्ता करना महत्वपूर्ण है। जब किसिंजर अपने पद पर थे तब उन्होंने चीन के नेताओं के साथ वार्ता की प्रक्रिया शुरु की थी।

चीन के साथ सम्पर्क में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि वे चीन व अमेरिकन सरकार के बीच मध्यस्थ थे। वे चीन के नेताओं का संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति तक ले जाते थे और अमेरिकन राष्ट्रपति का संदेश चीन तक। हमें दोनों देशों के बीच वार्ता करने के लिए और ज्यादा किरदार तलाशने होंगे। और दोनों सरकारों, सेना, आर्थिक अधिकारियों के बीच ज्यादा से ज्यादा बातचीत शुरु करनी होंगी, ताकि एक सतत समझ विकसित हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका मंजूर की। न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सीतलवाड़ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने और हिरासत में पूछताछ पूरी होने के तथ्य पर गौर करते हुए राहत दी।

शीर्ष अदालत ने साथ ही गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें सीतलवाड़ को जमानत देने से इनकार करने के साथ ही तत्काल आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था।शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए यह भी कहा कि यदि सीतलवाड़ की ओर से गवाहों को प्रभावित करने का मामला सामने आता है तो अभियोजन पक्ष उनकी जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने इससे पहले एक जुलाई को रात करीब 9:15 सुनवाई कर तीस्ता को एक सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी। पीठ ने सीतलवाड़ को तत्काल आत्मसमर्पण करने के गुजरात उच्च न्यायालय के कुछ घंटे पहले दिए आदेश पर रोक लगा दी थी। विशेष पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था, हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि एकल पीठ ने उन्हें एक सप्ताह की भी सुरक्षा न देकर सरासर गलत किया।

विशेष पीठ ने शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और प्रशांत कुमार मिश्रा की दो सदस्यीय पीठ के एक जुलाई को ही याचिकाकर्ता को अंतरिम सुरक्षा देने के मुद्दे पर मतभेद के कारण कुछ समय बाद ही रात करीब 9:00 बजे सुनवाई की थी।

प्र.मंत्री मोदी की सीकर की सभा में तीन लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य

जयपुर/नई दिल्ली, 19 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर आएंगे। मोदी जिला स्टेडियम में किसान सम्मान की 14 वीं किस्त जारी करेंगे। साथ ही बड़ी आमसभा को संबोधित करेंगे। शेखावाटी के जिले से बड़ी संख्या में किसान इस रैली में शामिल होने पहुंचेंगे। राजधानी जयपुर तक से बीजेपी नेता कार्यकर्ता और किसान मोदी की सभा में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर दौरे की तैयारियों को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सीकर में पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी। पहले यह रैली नागौर में आयोजित होने वाली थी लेकिन भाजपा ने रणनीतिक कारणों से इस रैली के वैन्यू में परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री अब नागौर की बजाय सीकर में पधारेंगे।

- प्रधानमंत्री 27 जुलाई को सीकर की इस रैली के मंच से ही किसान सम्मान की निधि 14वीं किस्त के तहत 30 हजार करोड़ रु. जारी करेंगे तथा साथ ही बड़ी आमसभा को संबोधित करेंगे
- प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन यहीं पर "पीएम प्रणाम" योजना की शुरुआत भी करेंगे।

सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिलाध्यक्ष के साथ उन्होंने सभास्थल जिला स्टेडियम का दौरा किया। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सीकर आएंगे। सीकर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को किसानों को सम्मान निधि की 14वीं किस्त करीब 30 हजार करोड़ रुपये का भुगतान सीधा किसानों के खातों में जारी करने के लिए सीकर जिला स्टेडियम में आएंगे।

उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि में अभी तक करीब 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये किसानों को भेजे जा चुके हैं। बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन यहीं पर पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत भी करेंगे।

प्रधानमंत्री की आमसभा में करीब तीन लाख से भी अधिक लोग आएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आम जनता, किसानों, जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर लागू करते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहां की जनता में अपार उत्साह है।

कर्नाटक सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत एक लोक कल्याणकारी देश है और यह सभी के हित पूरे करेगा अगर प्रधानमंत्री को यह याद होता तो वो भी आवश्यक वस्तुओं, एल.पी.जी. और पैट्रोल के दाम कम करके आम जनता की तकलीफ दूर करने का प्रयास करेंगे।

गृहलक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने इसकी शुरूआत की यह योजना एक साल चलेगी। कोई भी सैंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है अगर कुछ लोग सैंटर तक नहीं जा पाएंगे तो सरकारी कर्मचारी खुद उनके घर जाएंगे।

सभी महिलाएं चाहे वे बी.पी.एल. हों या ए.पी.एल. चाहे वे या उनके पति इन्कम टैक्स देते हों इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा था कि 5 चुनाव गारंटियों पर सालाना 52,000 करोड़ रू. खर्च किया जाएगा और इससे 1.3 करोड़ परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है।

अब यह स्पष्ट है कि कर्नाटक सरकार चुनावी वायदे पूरे करने की मुहिम में जुट गई है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले सुशासन का मॉडल पेश किया जा सके। इसी के साथ कांग्रेस ने फेक न्यूज़ को चेक करने, मॉरल पुलिसिंग पर नियंत्रण तथा हेट क्राइम को रोकने के लिए भी कदम उठाया शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ व राजस्थान सरकारों का फोकस भी लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर जो मतदाता को रिझा सकें।

लोकसभा चुनाव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल दलों की संख्या 26 थी। भाजपा के इस तामझाम को झटका देने वाला यह पक्ष भी है कि जिन पार्टियों के नेता दिल्ली की बैठक में शामिल हुये थे, उनका प्रभाव क्षेत्र (कैंचमैंट एरिया) काफी छोटा है।

दिल्ली की मीटिंग में अकेले पूर्वोत्तर राज्यों के ही 11 क्षेत्रीय दल शामिल हुये थे।

शिव सेना के एकनाथ शिंदे गुट तथा नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के अलावा, दिल्ली की मीटिंग में अन्नाद्रमुक, अपना दल (सोनेवाल), ए.जे.एस.यू., एस.बी.एस.पी., राष्ट्रीय समाज पक्ष, भारत धर्म जन सेना, निषाद पार्टी तथा लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट शामिल हुये थे।

इसके विपरीत, विपक्षी दलों की मीटिंग में वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, अरविन्द केजरीवाल, हेमन्त सोरेन तथा नीतीश कुमार के अलावा, अन्य कई वरिष्ठ एवं स्थापित नेता भी उपस्थित हुये थे, जिनमें शरद पवार, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद, राहुल गांधी, अखिलेश यादव तथा उद्धव ठाकरे शामिल थे।

विपक्ष व भाजपा के बीच "माइन्ड गेम्स"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"इंडिया" रखने पर प्रश्न खड़ा करना शुरु कर दिया है तथा कहा है कि "इंडिया" भारत से अलग है।

प्रधानमंत्री मोदी का अनुसारण करते हुये, सत्तारूढ़ भाजपा के अन्य नेताओं ने भी विपक्षी मोर्चे के बारे में अफवाहें फैलना शुरु कर दिया है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि हमारे साथी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की मीटिंग के बाद, प्रैस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुये बिना ही बैंगलुरु से रवाना हो गये क्योंकि वे नये गठबंधन के संयोजक नामजद नहीं किये जाने से अशांत (अपसैट) थे।

इस अनिष्टकारी टिप्पणी का तुरन्त जवाब देते हुए जनता दल (यू) ने सुशील मोदी की टिप्पणी पर प्रहार किया तथा कहा कि मुख्यमंत्री जल्दी इसलिए चले गये थे क्योंकि उन्हें अपनी फ्लाइट पकड़नी थी।

इस बीच यह बता दें कि नीतीश कुमार ने विचार विमर्श में बढ़-चढ़कर भाग लिया था क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति रहे, जिन्हें मोर्चा के नाम "इंडिया" रखे जाने पर कुछ आपत्ति थी लेकिन जब अन्य दलों के नेताओं ने उन्हें समझाया तो अन्त में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था।

मीटिंग के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की कि 2024 में सत्तारूढ़ भाजपा का मुकाबला करने की संयुक्त नीति की योजना बना रहे विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम आई.एन.डी.आई.ए. (इण्डिया) होगा, जो इंडियन नैशनल डवलपमैंटल इनक्लूसिव अलायंस" का संक्षिप्त रूप है।

चर्चा के दौरान, नीतीश कुमार ने पूछा बताते हैं कि विपक्षी गठबंधन का नाम "इंडिया" कैसे रखा जा सकता है। उनकी आपत्ति का एक कारण यह भी था कि आई.एन.डी.आई.ए. में "एन.डी.ए." अक्षर भी आते है तथा दोनों नाम एक ही प्रकार की ध्वनि वाले हैं। तभी किसी ने उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि इंडिया में दो बार "आई." अक्षर भी तो आ रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री ने कुछ नाम सुझाए थे, जैसे- "इंडिया मेन फ्रंट" तथा "इंडिया मेन अलांयस"।

"इंडिया" नाम को लेकर वामपंथी नेताओं में भी कुछ हिचकिचाहट थी तथा उन्होंने कुछ अलग विकल्प सुझाये थे, जैसे- "सेव इंडिया अलांयस" तथा "वी.फॉर इंडिया"।

चूँकि अधिकांश पार्टियाँ "इंडिया" का अनुमोदन करती प्रतीत हो रही थीं, कहा जा रहा है इसलिये नीतीश कुमार भी राजी हो गये।

बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, "ठीक है, अगर आप सब इसका (इंडिया) का समर्थन कर रहे हैं, तो यही ठीक है।"

एन.डी.ए. (नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) की समान ध्वनि वाले प्रथमाक्षर समूह में "डेमोक्रेटिक" शब्द पर भी कुछ चर्चा हुई थी। दोनों नामों को परस्पर और ज्यादा अलग करने के लिये, कांग्रेस ने सुझाव दिया कि "इंडिया" (आई.एन.डी.आई.ए.) को "डी" को "डवलपमैंट" के प्रथमाक्षर के रूप में लिया जाये।

भाजपा ने विभिन्न विपक्षी नेताओं के कथनों में "डेमोक्रेटिक" और "डवलपमैंटल" के बीच विभ्रम की स्थिति को लेकर विपक्ष की हँसी उड़ाई।

रिपोर्टों में "इंडिया" नाम का श्रेय ममता बनर्जी तथा राहुल गांधी को दिया गया है।

"विदुथलाई चिरुधाइगल काची" प्रमुख थोल तिरुमावालाान ने कहा कि इस नाम का सुझाव ममता बनर्जी ने दिया था।

उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नाम "इंडिया" ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया था। लम्बी चर्चा के बाद, यह तय हुआ है "इंडियन नैशनल डवलपमैंटल इनक्लूसिव अलायंस" कहा जाना चाहिये।

दूसरी तरफ एन.सी.पी. नेता जितेन्द्र अव्हाड़ की पोस्ट के अनुसार, यह विचार राहुल गांधी का था। पोस्ट में राहुल गांधी ने इस गठबंधन का नाम "इंडिया" रखने का प्रस्ताव रखा था। उनकी सृजनशीलता की काफी तारीफ हुई थी। सभी दलों ने इसका अनुमोदन कर दिया था तथा आगामी लोकसभा चुनाव "इंडिया" नाम के तहत लड़ने का निर्णय ले लिया गया था।

बताया जाता है कि राहुल गांधी ने इस नाम का सुझाव दिया तो था लेकिन यह निर्णय ले लिया गया था कि ममता बनर्जी इस नाम का प्रस्ताव विधिवत रखें। प्रैस-ब्रीफिंग के दौरान, गठबंधन के नाम के विषय में बोलते हुये, बंगाल की मुख्यमंत्री ने "हमारे प्रिय राहुल गांधी" का संदर्भ दिया था।

जैसे ही भाजपा ने इस नाम पर हमला बोलते हुय, "इंडिया" को "भारत" के मुकाबले में खड़ा किया, वैसे ही विपक्षी मोर्चा ने आज इसकी टैग लाइन "जीतेगा भारत" घोषित कर दी।

यह टैग लाइन कल देर रात गये हुई विस्तृत चर्चा के बाद तय की गई। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे ने यह सुझाव दिया कि गठबंधन की टैग लाइन हिन्दी में होनी चाहिये।

विपक्ष की अगली मीटिंग मुम्बई में होगी तथा इसकी मेजबानी उद्धव ठाकरे का शिव सेना गुट करेगा।

गठ विपक्षी दलों के नेताओं ने इस बिन्दु पर भी चर्चा की कि गठबंधन का चेहरा कौन हो।

इस तथा ऐसे ही अन्य मुद्दों पर निर्णय 11 सदस्यों की वह समन्वय समिति लेगी, जिसमें सभी बड़े दल शामिल होंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि गठबंधन के प्रचार-प्रबंधन के लिये दिल्ली में एक "सचिवालय" भी स्थापित किया जायेगा।

भाजपा के 10 विधायक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के जिन 10 विधायकों को निलंबित किया है वे हैं- डॉ. सी एन अश्वथ नारायण, वी सुनील कुमार, आर अशोक, अरागा ज्ञानेंद्र (सभी पूर्व मंत्री), डी वेदव्यास कामथ, यशपाल सुवर्ण, धीरज मुनिराज, ए उमानाथ कोटियन, अरविंद बेलाड और वाई भरत शेट्टी। विधानसभा सत्र 3 जुलाई को शुरू हुआ और 21 जुलाई को समाप्त होने वाला है। अध्यक्ष ने कहा, मैं उनके (10 विधायकों) नाम उनके अशोभनीय और असम्मानजनक आचरण के कारण ले रहा हूं। बेहद पीड़ा के साथ मैं इस प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रख रहा हूं। इसके बाद ध्वनि मत के आधार पर 10 सदस्यों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। दरअसल, कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने आसन की तरफ कागज फेंके। भाजपा विधायक भोजन अवकाश के बिना सदन की कार्यवाही संचालित करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से नाराज थे। यह बीते 2 दिन में बैठक के लिए कांग्रेस सरकार की ओर से आईएएस अधिकारियों के दुरुपयोग को लेकर भाजपा के विरोध के बीच हुआ। अध्यक्ष यूटी खादेर यह कहकर चले गए कि सदन में भोजन अवकाश नहीं होगा और बजट व मांगों पर चर्चा जारी रहेगी, जिसके बाद उपाध्यक्ष रुद्राप्पा लमानी सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908